

प्रषक,

निधि मणि त्रिपाठी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 05 दिसम्बर, 2014

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय महाविद्यालय लक्सर के भवन निर्माण के कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निमग लि0 हरिद्वार इकाई के पत्र संख्या-561/रा0नि0नि0/एच-12 2014 दिनांक 02.09.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय महाविद्यालय लक्सर जनपद हरिद्वार के भवन निर्माण के प्रथम चरण के कार्यों हेतु परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 4.90 लाख (रू0 चार लाख बाहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगा। तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक माह के भीतर पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर समक्ष अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5- कार्य करने से पूर्व औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

7- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करे।

8- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

9- यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

10- प्रथम चरण के कार्यों हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिकरूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

- 11- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 12- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय।
- 13- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 14- स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। प्रथम चरण के प्रक्रियात्मक कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxviii(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयवद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या देते हुए द्वितीय चरण के लिए निर्धारित प्रक्रियानुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 15- तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्ज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।
- 16- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 17- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-आयोजनागत-03-कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना/नये भवन निर्माण (एस.पी.ए.)-24-बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 18- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-228(P)/xxvii(3)/2014-15 दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(निधि मणि त्रिपाठी)
प्रभारी सचिव।

पू0सं0322(1)/xxiv(7)-40(2)/2014तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 4- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 5- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय लक्सर जनपद हरिद्वार।
- ✓ 6- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
- 7- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
- 8- वित्त अनु0-3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 9- प्ररियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 राजकीय नि0नि0लि0 हरिद्वार इकाई जनपद हरिद्वार।
- 10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।